भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4540

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

'जल उपयोग दक्षता ब्यूरो' की स्थापना

4540. श्रीमती हेमा मालिनी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने, विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए अक्तूबर 2022 में राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत 'जल उपयोग दक्षता ब्यूरो' की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को बीस प्रतिशत तक बढ़ाना था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है तथा 'जल उपयोग दक्षता ब्यूरों' के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां, केन्द्रीय जल आयोग के मौजूदा निदेशालय का पुनर्गठन किया गया है तथा राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है।

(ख): राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों में से एक अर्थात जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल के कुशल उपयोग के लिए "राष्ट्रीय जल मिशन" योजना के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (कार्यालय आदेश पर उपलब्ध है) की स्थापना की गई है।

सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम तथा बीडब्ल्यूयूई द्वारा अब तक हासिल की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

क. **उद्योग क्षेत्र में बेंचमार्क अध्ययन:** औद्योगिक जल उपयोग को बेंचमार्क करने और औद्योगिक जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए नीति बनाने में सहायता करने के लिए "ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी)" के माध्यम से एक बेंचमार्किंग अध्ययन किया गया। चार औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया अर्थात थर्मल पावर प्लांट और टेक्सटाइल तथा पल्प एवं पेपर और स्टील उद्योग।

ख. **सिंचाई क्षेत्र में बेसलाइन अध्ययन:** 3 संस्थानों अर्थात् वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर वॉटर रिसोर्सेस डेवेलपमेंट एंड मैनेजमेंट के माध्यम से बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता का मूल्यांकन

करने के लिए 4 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र में 17 बेसलाइन अध्ययन किए गए।

ग. **सही फसल अभियान:** इसे जल संकट वाले क्षेत्रों में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दिनांक 14.11.2019 को राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया और जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, लघु कृषक कृषि कंसोर्टियम (एसएफएसी) और अटल भूजल योजना के सहयोग से 14 अभियानों में से अब तक 12 सही फसल अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।

घ. **2 कार्यशालाएँ/सम्मेलन:** (i) भारतीय प्लंबिंग एसोसिएशन (आईपीए) के सहयोग से घरेलू जल क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 27.01.2025 को **"जल उपयोग दक्षता: एक सतत भविष्य के लिए रणनीतियाँ"** शीर्षक से एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें (ii) दिनाँक 12.03.2025 को "जल स्थिरता सम्मेलन 2025" शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के सहयोग से औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ङ. **एसडीजी संकेतक के संबंध में देश की रिपोर्ट:** खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को वर्ष 2023 के लिए एसडीजी संकेतक 6.4.1 (समय के साथ जल उपयोग दक्षता में परिवर्तन) और एसडीजी 6.4.2 (जल संकट का स्तर) पर अनंतिम देश रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

च. **राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) और भारतीय प्लंबिंग एसोसिएशन (आईपीए) के बीच समझौता ज्ञापन:** घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) बढ़ाने सहित एनडब्ल्यूएम लक्ष्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करने हेतु एनडब्ल्यूएम और आईपीए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

*****